Rajasthan, Government will consider the desirability of locating this project somewhere in that State and thus give an impetus to the wool breeding programme which will considerably ameliorate the economy of the poor tribals and other weaker sections in that State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SUPPLY AND TEXTILES (SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH): (a) and (b) A Study group was appointed to study the problems of wool and woollen Industry. In its Report, the Study Group had *inter-alia*, recommded constitution of a Wool Board. An Inter-Ministerial 'Empowered Committee' under the Chairmanship of Secretary (Textiles) was constituted by the Government to take decisions for effective and expeditious implementation of the recommendation made in the said Report. The decisions of the Empowered Committee have been finalised recently, and the Committee has decided to constitute a Wool Board for an integrated development of the Woollen Textile Industry.

(c) Wool Board is constituted for integrated and harmonious development of all the sectors of Woollen Textile Industry. Its location would be decided keeping in view the requirements and convenience of all sectors of Woollen Textile Industry.

हिन्दी सलाहकार समिति का गठन

13. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी तक हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया गया है, यदि हां तो इसके क्या कारण है ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि आवश्यक हिन्दी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की अनुमति नहीं दी जा रही है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) जी, नहीं। एक संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति के स्थान पर दो अलग-अलग हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। एक व्यय विभाग और राजस्व विभाग के लिए और दूसरी बैंकिंग और बीमा सहित आर्थिक कार्य विभाग के लिए।

(ख) वित्त मंत्रालय के तीनों विभागों में से प्रत्येक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पदनाम के आधार पर की जाती है।

(ग) जनवरी, 1984 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मुद्रा-स्फीति निरोधक उपायों के एक भाग के रूप में आगामी आदेशों तक वर्तमान रिक्तियों को न भरने की सलाह दी गई थी। तथापि, इन आदेशों के अन्तर्गत निम्न पद से पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा रिक्तियों को भरने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अन्तर्गत 550-800/- रु० और ऊपर के ग्रेड में हिन्दी पद कुल मिलाकर निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा भरे जाते हैं। इसलिए इस सीमा तक इन ग्रेडों में रिक्तियों को भरे जाने में कोई कठिनाई नहीं है।

टसर और मूंगा रेशम का निर्यात

14. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलबरी रेशम के मुकाबले टसर और मूंगा रेशम का निर्यात हुआ है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी रेशम के निर्यात के मामले में स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि टसर और मूंगा रेशम के निर्यात में गिरावट इसके कम उत्पादन के कारण आई है; यदि हां, तो सरकार इनका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ;

(ग) क्या यह सच है कि टसर और मूंगा किस्मों का रेशम केवल, बिहार, मध्य प्रदेश और असम के राज्यों में उपलब्ध है जहां तक रेशम

बोर्ड की पहुंच नहीं है चूंकि वे इसके मुख्यालय से बहुत दूर है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) चूंकि शहतूती रेशम विश्व में रेशम उत्पादन तथा खपत की प्रमुख किस्म है, अतः इस किस्म का निर्यात रेशम की अन्य किस्मों की अपेक्षा अधिक है । ऐरी रेशम का उत्पादन सीमित है तथा इस प्रकार इसका निर्यात नगण्य है ।

(ख) टसर रेशम के निर्यात में कोई कमी नहीं हुई हैं तथा वास्तव में, 1984-85 वर्ष के दौरान 1983-84 के आंकड़ों की तुलना में इन निर्यातों के मूल्यों में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यद्यपि रेशम का उत्पादन बढ़ रहा है, परन्तु यह अभी भी बहुत सीमित हैं तथा इस किस्म का निर्यातों लगभग नगण्य है । टसर का उत्पादन बढ़ाने के लिये 10.5 करोड रु० के परिव्यय से आठ राज्यों में 6737 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एक अन्तर्राज्यीय टसर परियोजना पहले से ही शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा, 3.5 करोड रु० के परिव्यय से देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मूंगा बीज के विकास के लिये एक योजना भी क्रियान्वित की जा रही है ।

(ग) बिहार, मध्य प्रदेश तथा असाम के अतिरिक्त कच्चे रेशम की गैर शहतूती किस्म का उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा मणिपुर । केन्द्रीय रेशम बोर्ड की इन राज्यों में राज्य विभागों के साथ निकट समन्वय सुनिश्चित करने के लिये क्षेत्रीय विकास कार्यालयों, अन्वेषण उप-स्टेशनों तथा विस्तार केन्द्रों की व्यवस्था है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेशम बोर्ड के मुख्यालय को अन्यत्र ले जाया जाना

15. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेशम उद्योग के हित में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मुख्यालय को बदल कर दिल्ली लाने जो कि एक केन्द्रीय स्थान है या फिर इसे बम्बई ले जाने, जहां कि यह पहले भी अवस्थित था, का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या टसर, मूंगा और ऐरी रेशम के उत्पादन के संवर्धन के लिये कोई स्थायी समिति गठित की गयी है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तथा (ख) जी नहीं ।

Sick Textile mills in the country

16. DR. SHYAM SUNDAR MOHAPATRA: Will the Minister of SUPPLY AND TEXTILES be pleased to state:

(a) what is the number of sick textile mills in the country as at present;

(b) what is the number of such mills which have since been revived; and

(c) what is the number of textile mills which are still languishing?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SUPPLY AND TEXTILES (SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH): (a) to (c) The total number of closed cotton textile mills in the country as on 30.6.85 is 66. A monitoring mechanism has been instituted to detect the causes of incipient sickness of the units of industry and the number of sick mills will depend upon an objective evaluation with reference to relevant parameters at any given point of time.